



राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम (NLMC)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम \(NLMC\)](#) के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इसे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) की अधिशेष भूमि जोत के मुद्राकरण के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में घोषित किया था।

राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम (NLMC) क्या है?

- **स्वामित्व:** NLMC एक ऐसी फर्म होगी जिसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार के पास होगा। यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आएगी।
- **प्रारंभिक पूंजी:** इसे ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और ₹150 करोड़ की पेड अप पूंजी के साथ स्थापित किया जाएगा।
- **NLMC के कार्य:**
 - **संपत्तिका मुद्राकरण:** NLMC सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तिका अधिशेष, अपरयुक्त भूमिका संपत्तिका के रूप में मुद्राकरण करेगा।
 - **सामरिक वनिविश:** नगिम इन भूमि जोत के मूल्य को अनलॉक करने के उद्देश्य से उन सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित संपत्तियों के मुद्राकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा जो परिचालन बंद कर चुके हैं या सामरिक वनिविश के लिये लाइन में हैं।
 - ऐसे उद्यमों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्तिका NLMC को हस्तांतरित किये जाने की उम्मीद है, जो तब उन्हें धारण, प्रबंधन और मुद्राकृत करेगी।
- **सलाहकार की भूमिका:** NLMC एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा और अन्य सरकारी संस्थाओं एवं CPSE को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख संपत्तियों की पहचान करने तथा उन्हें कुशल और पेशेवर तरीके से मुद्राकृत करने, मूल्य प्राप्ति के दायरे को अधिकतम करने में सहायता करेगा।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं की निर्देशिका:** NLMC एक एजेंसी द्वारा किये जाने वाले कार्य के रूप में मुद्राकरण करेगा और भूमि मुद्राकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं की निर्देशिका के रूप में कार्य करने की उम्मीद है।
 - NLMC राष्ट्रीय नविश और बुनियादी ढाँचा कोष (NIIIF) तथा इन्वेस्ट इंडिया जैसी अन्य वशिष्ट सरकारी कंपनियों के समान योग्यता आधारित दृष्टिकोण के साथ नज्दी क्षेत्र के पेशेवरों को नियुक्त करेगा।
 - ऐसा इसलिए है क्योंकि अचल संपत्तिका मुद्राकरण के लिये संपत्तिका के मूल्यांकन, बाजार अनुसंधान, नविश बैंकगि, भूमि प्रबंधन, कानूनी कार्य और अन्य संबंधित कौशल हेतु वशिष्टज्ञता की आवश्यकता होती है।

मुद्राकरण का क्या अर्थ है?

- **मुद्राकरण के बारे में:** जब सरकार अपनी संपत्तिका मुद्राकरण करती है, तो इसका अनविर्य रूप से मतलब है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिये संपत्तिका के राजस्व अधिकारों को नज्दी संस्था को हस्तांतरित कर रही है।
 - इस तरह के लेन-देन में सरकार को नज्दी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्तिका से उत्पन्न राजस्व का नियमित हिस्सा, परिसंपत्तिका में स्थिर नविश का वादा और मुद्राकृत संपत्तिका के टाइटल अधिकार मिलते हैं।
- **मुद्राकरण के तरीके:** सरकारी संपत्तियों का मुद्राकरण करने के कई तरीके हैं;
 - कार्यालयों जैसे कुछ स्थानों के भूमि मुद्राकरण के मामले में यह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT), एक कंपनी जो भूमि संपत्तिका की मालिक है और इसका संचालन करती है, के माध्यम से किया जा सकता है।
 - पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के ज़रिये सरकार की संपत्तिका मुद्राकरण भी किया जा सकता है।

मुद्राकरण का कारण:

- सरकार राजस्व के नए स्रोत बनाने के लिये अपनी संपत्तिका मुद्राकरण करती है।
- संस्थागत नविशकों या नज्दी क्षेत्र को शामिल करके अपरयुक्त या कम उपयोग की गई संपत्तिका की क्षमता को अनलॉक करने के लिये भी मुद्राकरण किया जाता है।

- यह कार्य भविष्य के संपत्ति निर्माण के लिये संसाधन या पूंजी उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है, जैसे कम्प्यूटरीकरण से उत्पन्न धन का उपयोग नए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्माण के लिये करना।

मुद्रीकरण के लिये वर्तमान में कतिनी भूमि उपलब्ध है?

- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार, अब तक CPSE ने लगभग 3,400 एकड़ ज़मीन के संभावित मुद्रीकरणका का प्रस्ताव रखा है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, सार्वजनिक उपकरणों की गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण विभिन्न चरणों में है:
 - उदाहरण के लिये मार्च 2020 में बीएसएनएल ने मुद्रीकरण के लिये कुल ₹24,980 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की पहचान की थी।
 - इस बीच रेलवे और रक्षा मंत्रालयों के पास देश में सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीन है।
 - रेलवे के पास 11 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है, जसमें से 1.25 लाख एकड़ ज़मीन खाली है।
 - रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ ज़मीन है। इसमें से लगभग 1.6 लाख एकड़ ज़मीन 62 सैन्य छावनियों के अंदर आती है, जबकि 16 लाख एकड़ से अधिक छावनी की सीमाओं के बाहर है।

NLMC की संभावित चुनौतियाँ क्या हैं?

- विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव।
- सरकारी कंपनियों में नज़ीकरण की धीमी रफ़्तार।
- ट्रेनों में हाल ही में शुरू की गई सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी (पीपीपी) पहल में कम बोलियाँ इंगति करती हैं कि नज़ी नविशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है।
- संपत्ति-विशिष्ट चुनौतियाँ:
 - गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का नमिन स्तर।
 - वदियुत क्षेत्र की परिसंपत्तियों में वनियमिति टैरफि।
 - फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में नविशकों की दलिचस्पी कम।

आगे की राह

- अवसंरचना वसितार योजना की सफलता अन्य हतिधारकों द्वारा उनकी उचित भूमिका नभाने पर निर्भर करेगी।
- इनमें राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा नज़ी क्षेत्र शामिल हैं।
- इस संदर्भ में पंद्रहवें वलित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के वलित्तीय उत्तरदायित्व कानून की फरि से जाँच करने के लिये एक उच्चधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह की स्थापना की सफिरशि की है।
- पारदर्शिता बनाए रखना परिसंपत्ति मूल्य की पर्याप्त प्राप्ति की कुंजी है।
- हाल के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी (पीपीपी) में अब पारदर्शी नीलामी, जोखमिों और अदायगी की स्पष्ट समझ एवं सभी इच्छुक पार्टियों के लिये एक खुला क्षेत्र शामिल है।
- इस प्रकार ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में पीपीपी की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- सरकार को एक कुशल वविाद समाधान तंत्र स्थापति करना चाहिये।

वनिविश क्या है?

- वनिविश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्ति की बकिरी या परसिमापन। आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएँ या अन्य अचल संपत्ति।
- सरकार राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करने या वशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन जुटाने हेतु वनिविश करती है, जैसे कि अन्य नयिमति स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करना।
- सामरिक वनिविश एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नयित्रण को कसिी अन्य इकाई (ज्यादातर नज़ी क्षेत्र की इकाई को) का हस्तांतरण है।
- साधारण वनिविश के वपिरीत रणनीतिक बकिरी का तात्पर्य एक प्रकार का नज़ीकरण है।
- वनिविश आयोग रणनीतिक बकिरी को एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) के 50% तक के सरकारी शेरधारता के एक बड़े हसिसे की बकिरी के रूप में परभाषति करता है या परबंधन नयित्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सकषम प्राधिकारी द्वारा नरिधारति उच्च परतशित के रूप में।
- वलित्त मंत्रालय के तहत नविश और सार्वजनिक संपत्ति परबंधन वविाग (DIPAM) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों (PSU) में रणनीतिक हसिसेदारी की बकिरी के लिये नोडल वविाग है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) क्या है?

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) शुरू की है।
- यह चार साल की अवधि (वलित्त वर्ष 2022-25) में सड़कों, रेलवे, बजिली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों को पट्टे पर देकर ₹6 लाख करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परकिल्पना करता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. शासन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (वर्ष 2010)

1. परत्यक्ष वदिशी नविश प्रवाह को प्रोत्साहति करना
2. उच्च शकिषण संस्थानों का नजीकरण
3. नौकरशाही का आकार कम करना
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बकिरी/ऑफलोडगि

भारत में राजकोषीय घाटे को नयितरति करने के उपायों के रूप में उपरोक्त में से कसिका उपयोग कथि जा सकता है?

- (A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 3 और 4

उत्तर: (D)

प्रश्न. हाल ही में खबरों में रहे 'स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरगि ऑफ स्ट्रेसड एसेट्स (S4A)' शब्द का सबसे अच्छा वर्णन नमिनलखिति कथनों में से कौन सा है? (2017)

- (A) यह सरकार द्वारा तैयार की गई वकिस योजनाओं की पारस्थितिकि लागत पर वचिर करने की एक प्रकरयि है।
(B) यह वास्तवकि कठनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं की वत्तीय संरचना को फरि से कार्यरत बनाने के लयि आरबीआई की एक योजना है।
(C) यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की एक वनिविश योजना है।
(D) यह हाल ही में सरकार द्वारा लागू 'दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैकरप्सी कोड' में एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

उत्तर: (B)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-land-monetisation-corporation>